PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 223
दि. 17.05.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

फर्जी डिग्री और बयान पर विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की सफाई, कहा युवाओं पर नहीं बल्कि सिस्टम में घुसपैठ करने वालों पर थी टिप्पणी

नई दिल्ली। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के एक मौखिक टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब उनकी विस्तृत सफाई के बाद नए मोड़ पर पहुंच गया है। अदालत में एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई उनकी टिप्पणी को लेकर मीडिया के एक वर्ग में यह धारणा बन गई थी कि उन्होंने युवाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस पर उठे राजनीतिक और सामाजिक विवाद के बाद सीजेआई ने स्पष्ट किया है कि उनकी बात देश की युवा पीढ़ी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उन लोगों के खिलाफ थी जो फर्जी और जाली डिग्रियों के सहारे विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में प्रवेश कर सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

सीजेआई सूर्यकांत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया, जिससे गलतफहमी पैदा हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से गहरा दुख हुआ है कि एक सामान्य सुनवाई के दौरान कही गई बात को तोड़-मरोड़कर इस तरह प्रस्तुत किया गया कि जैसे उन्होंने पूरे युवा वर्ग पर टिप्पणी की हो। उन्होंने दोहराया कि उनका उद्देश्य किसी भी स्थिति में युवाओं का अपमान करना नहीं था, बल्कि न्यायिक और पेशेवर व्यवस्था में हो रही अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त करना था।

सीजेआई ने कहा कि फर्जी और जाली शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर कई लोग वकालत जैसे गंभीर और जिम्मेदारी वाले पेशों में प्रवेश कर जाते हैं, जो न केवल न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है बल्कि आम जनता के विश्वास को भी कमजोर करता है। उन्होंने इसे एक गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि ऐसे लोग केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में भी देखे जा सकते हैं, जहां बिना योग्यता और सत्यापन के लोग सक्रिय हो जाते हैं और व्यवस्था को प्रभावित करने की

कोशिश करते हैं।

अपने बयान में सीजेआई ने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी वर्ग या पीढ़ी को लक्षित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भारत का युवा देश का सबसे बड़ा संसाधन है और वह हमेशा युवाओं की क्षमता, ऊर्जा और भविष्य की संभावनाओं पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय युवा न केवल देश की प्रगति के स्तंभ हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह से यह समझना कि उनकी टिप्पणी युवाओं के खिलाफ थी, पूरी तरह गलत और भ्रामक है।

सीजेआई ने यह भी कहा कि अदालत में दिए गए उनके शब्दों का उद्देश्य एक व्यापक सामाजिक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना था, जिसमें बिना उचित योग्यता के लोग विभिन्न पेशों में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की जिम्मेदारी केवल मामलों का निपटारा करना ही नहीं, बल्कि समाज में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने से जुड़े मुद्दों पर भी गंभीर टिप्पणी करना होता है। इसी संदर्भ में उन्होंने यह बात कही थी, जिसे कुछ लोगों ने गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया। इस पूरे मामले की शुरुआत उस समय हुई जब एक सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने वकालत और अन्य पेशों में गिरावट को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। अदालत में उन्होंने व्यवस्था में आ रही गिरावट और कुछ लोगों के बिना योग्यता के प्रवेश को लेकर चिंता जताई थी। इसी दौरान उन्होंने तीखी भाषा का उपयोग करते हुए सिस्टम में मौजूद "परजीवी तत्वों" का जिक्र किया था और यह भी कहा था कि कुछ लोग बिना क्षमता के मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य क्षेत्रों में जाकर व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे युवाओं के खिलाफ बयान के रूप में पेश किया जाने लगा, जिससे विवाद खड़ा हो गया। विवाद बढ़ने के बाद कई कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने कहा कि न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति के शब्दों की गंभीरता अधिक होती है और इसलिए उनके बयान को सावधानीपूर्वक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना था कि सीजेआई की टिप्पणी को संदर्भ से अलग करके गलत तरीके से प्रचारित किया गया, जिससे अनावश्यक विवाद पैदा हुआ। सीजेआई की सफाई के बाद अब इस मामले में विवाद काफी हद तक शांत होता नजर आ रहा है, हालांकि सोशल मीडिया पर अब भी इस मुद्दे को लेकर बहस जारी है। कई लोग यह कह रहे हैं कि न्यायिक टिप्पणी को पूर्ण संदर्भ में समझना जरूरी है, जबकि कुछ लोग अब भी उनके शब्दों के चयन पर सवाल उठा रहे हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला एक बार फिर इस बात को रेखांकित करता है कि अदालतों में कही गई मौखिक टिप्पणियों को मीडिया किस तरह प्रस्तुत करता है, उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। न्यायिक प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होने वाली भाषा अक्सर तकनीकी और संदर्भ आधारित होती है, लेकिन जब उसे सार्वजनिक विमर्श में लाया जाता है तो उसका अर्थ बदल सकता है।

सीजेआई ने अपने बयान में अंत में यह भी स्पष्ट किया कि वह देश की युवा शक्ति पर अटूट विश्वास रखते हैं और उन्हें विकसित भारत के निर्माण का सबसे मजबूत आधार मानते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी चिंता केवल उन तत्वों को लेकर है जो व्यवस्था में गलत तरीकों से प्रवेश कर समाज और संस्थानों को नुकसान पहुंचाते हैं।

इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर न्यायपालिका, मीडिया और सार्वजनिक संवाद के बीच संतुलन की आवश्यकता को उजागर किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि संवेदनशील संस्थागत बयानों को बिना पूरे संदर्भ के प्रस्तुत करना गलतफहमियों को जन्म दे सकता है, जिसका असर न केवल संबंधित व्यक्ति पर बल्कि पूरे समाजिक विमर्श पर पड़ता है।

NEET पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, सीबीआई ने पुणे की शिक्षिका को मास्टरमाइंड बताकर किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों को एक और बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में कथित रूप से मास्टरमाइंड मानी जा रही पुणे की एक बॉटनी शिक्षिका को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले की जांच एक बार फिर तेज हो गई है और शिक्षा तंत्र की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

सीबीआई द्वारा गिरफ्तार की गई आरोपी की पहचान पुणे निवासी वरिष्ठ बॉटनी शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंधारे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह नीट परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी विशेषज्ञ समिति का हिस्सा थीं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा विषय विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थीं। इस पद के चलते उन्हें बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्नपत्रों से जुड़े कुछ संवेदनशील हिस्सों तक पहुंच प्राप्त थी, जिसका कथित रूप से दुरुपयोग किया गया।

जांच एजेंसियों के अनुसार, यह पूरा नेटवर्क योजनाबद्ध तरीके से संचालित किया जा रहा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अप्रैल 2026 के दौरान आरोपी शिक्षिका ने पुणे में कुछ छात्रों को विशेष कोचिंग के नाम पर एकत्र किया था। इन कक्षाओं में कथित तौर पर नीट अभ्यर्थियों को बॉटनी और जूलॉजी के महत्वपूर्ण

प्रश्नों से संबंधित संकेत और तैयारियां करवाई जाती थीं। आरोप है कि छात्रों को नोटबुक और पाठ्यपुस्तकों में विशेष रूप से कुछ विषयों को चिन्हित करने के लिए कहा गया था।

सीबीआई सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान यह भी पाया गया कि इन चिन्हित प्रश्नों में से कई वास्तविक नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र से मेल खाते हैं। इस तथ्य ने जांच को और गंभीर बना दिया है क्योंकि इससे पेपर लीक या प्रश्नपत्र की पूर्व जानकारी साझा किए जाने की आशंका को बल मिलता है।

इस पूरे मामले में एक और आरोपी मनीषा वाघमारे का नाम भी सामने आया है, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में यह सामने आया है कि दोनों के बीच मिलकर एक संगठित नेटवर्क बनाया गया था, जिसके माध्यम से कुछ चुनिंदा छात्रों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। सीबीआई का मानना है कि यह केवल स्थानीय स्तर का मामला नहीं बल्कि एक व्यापक रैकेट का हिस्सा हो सकता है, जिसकी कड़ियां अन्य राज्यों तक फैली हो सकती हैं।

पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने इस मामले से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर सहित कुल छह स्थानों पर की गई कार्रवाई में जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं। इनमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैंक लेन-देन के रिकॉर्ड और संदिग्ध नोटबुक शामिल हैं। इन सभी सामग्रियों का फॉरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है ताकि पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा सकें।

अब तक इस मामले में कुल नौ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें कोचिंग सेंटर से जुड़े लोग, कुछ बिचौलिए और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े संदिग्ध व्यक्ति शामिल बताए जा रहे हैं। इनमें से पांच आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है ताकि उनसे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी हासिल की जा सके।

जांच एजेंसियों के अनुसार, हाल ही में गिरफ्तार किए गए दो अन्य आरोपियों को पुणे की अदालत से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दिल्ली लाया गया है, जहां उन्हें विशेष अदालत में पेश किया जा रहा है। सीबीआई अब इन सभी आरोपियों से आमने-सामने पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परीक्षा प्रणाली तक जानकारी कैसे पहुंची और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

इस मामले ने एक बार फिर देश की परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में पेपर लीक या गोपनीय जानकारी के लीक होने की आशंका ने लाखों छात्रों और अभिभावकों को चिंता में डाल दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि परीक्षा प्रणाली के भीतर से ही कोई व्यक्ति इस तरह की संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग करता है, तो यह पूरी व्यवस्था के लिए एक गंभीर चेतावनी है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों को रोकने के लिए केवल सख्त कानून ही नहीं, बल्कि तकनीकी सुरक्षा उपायों को भी मजबूत करना जरूरी है। डिजिटल प्रश्नपत्र प्रणाली, एन्क्रिप्शन और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग जैसे उपायों को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सीबीआई अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं क्योंकि जांच अभी शुरुआती चरण में है।

केरल कांग्रेस में सियासी खींचतान के बाद मेल-मिलाप की तस्वीर सतीशन-वेणुगोपाल की मुलाकात से एकता दिखाने की कोशिश

कोच्चि। केरल कांग्रेस में पिछले कई दिनों से चल रहे नेतृत्व संघर्ष और अंदरूनी खींचतान के बाद अब पार्टी ने सार्वजनिक रूप से एकजुटता का संदेश देने की कोशिश शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए वी.डी. सतीशन और एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की तिरुवनंतपुरम में हुई मुलाकात को कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। नेतृत्व की दौड़ में चली लंबी रस्साकशी और आखिरी क्षण तक बने सस्पेंस के बाद यह पहली बार था जब दोनों वरिष्ठ नेता खुलकर साथ नजर आए। कांग्रेस नेतृत्व इस मुलाकात के जरिए यह संदेश देना चाहता है कि मुख्यमंत्री चयन को लेकर पार्टी के भीतर जो मतभेद दिखाई दे रहे थे, अब उन्हें पीछे छोड़ दिया गया है और पूरा संगठन नई सरकार के गठन तथा प्रशासनिक कामकाज पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

केरल में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की वापसी के साथ ही मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी के भीतर तीखी लॉबिंग और शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला था। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और नव-निर्वाचित विधायकों के अलग-अलग खेमों में बंटे होने की चर्चा लगातार होती रही। राजनीतिक गलियारों में यह माना जा रहा था कि एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल को विधायकों के एक बड़े वर्ग का समर्थन हासिल

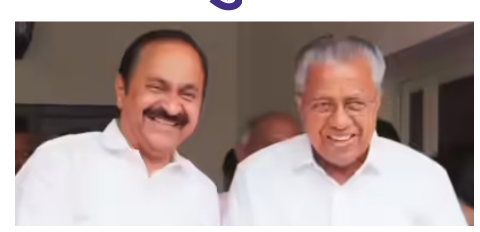

था और वे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। वहीं विपक्ष के नेता रहे वी.डी. सतीशन को संगठन और आलाकमान के भीतर प्रभावशाली समर्थन प्राप्त था। कई दौर की बैठकों और मंथन के बाद आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने सतीशन के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी।

मुख्यमंत्री पद के फैसले के बाद पार्टी के भीतर असंतोष और मतभेद की चर्चाएं और तेज हो गई थीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि यदि कांग्रेस नेतृत्व ने समय रहते स्थिति को संभाला नहीं, तो नई सरकार बनने से पहले ही पार्टी गुटबाजी का शिकार हो सकती है। ऐसे माहौल में सतीशन और वेणुगोपाल की मुलाकात को नुकसान नियंत्रण की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दोनों नेताओं ने बैठक के दौरान जिस तरह सार्वजनिक रूप से सकारात्मक संकेत दिए, उससे पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ सामान्य है।

तिरुवनंतपुरम में वेणुगोपाल के आवास पर हुई यह बैठक करीब एक घंटे तक चली। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया से बातचीत में किसी भी तरह के मतभेद की खबरों को खारिज कर दिया। एआईसीसी महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो राजनीतिक चर्चाएं हुईं, वे अब अतीत की बात हैं और कांग्रेस पूरी तरह एकजुट होकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि केरल की जनता ने कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन पर भरोसा जताया है, इसलिए अब पार्टी की प्राथमिकता स्थिर और प्रभावी सरकार देना है। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा होना कांग्रेस की परंपरा रही है और नेतृत्व चयन की प्रक्रिया भी उसी परंपरा का हिस्सा थी।

मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए वी.डी. सतीशन ने भी पार्टी में किसी प्रकार के टकराव या गुटबाजी की बातों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सभी फैसले सामूहिक चर्चा और विचार-विमर्श के बाद लिए जाते हैं। सतीशन ने मीडिया के एक वर्ग पर आरोप लगाया कि वह नेताओं के बीच मतभेदों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ा संगठन है और यहां अलग-अलग राय होना स्वाभाविक है, लेकिन अंतिम निर्णय होने के बाद सभी नेता एक साथ मिलकर काम करते हैं। सतीशन ने स्पष्ट किया कि पार्टी के भीतर ऐसा कोई विवाद नहीं है जिसे बातचीत और संगठनात्मक प्रक्रिया से हल न किया जा सके।

इस मुलाकात के राजनीतिक मायने इसलिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि नई सरकार के गठन को लेकर पार्टी के भीतर कई स्तरों पर बातचीत जारी है। मुख्यमंत्री पद के बाद अब मंत्रिमंडल गठन को लेकर भी विभिन्न गुट सक्रिय बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और विधायक मंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी नेतृत्व के सामने क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के साथ-साथ संगठनात्मक समीकरण साधने की बड़ी चुनौती है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आलाकमान इस बार मंत्रिमंडल में अनुभवी नेताओं और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।

सतीशन ने संकेत दिया है कि मंत्रिमंडल की सूची लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि सभी नामों पर चर्चा पूरी होने के बाद अंतिम सूची कांग्रेस आलाकमान की मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने बताया कि रविवार दोपहर तक मंत्रियों की अंतिम सूची सौंपे जाने की संभावना है और यदि सब कुछ तय समय के अनुसार हुआ तो सोमवार को पूरी कैबिनेट शपथ ले सकती है।

अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई, 182 करोड़ की कैप्टागन जब्त; एनसीबी ऑपरेशन से खुला बड़ा सिंडिकेट

नई दिल्ली। देश में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को एक बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी कि एजेंसी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले ड्रग सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 182 करोड़ रुपये मूल्य की कैप्टागन ड्रग की खेप जब्त की है। इस ऑपरेशन को नशा तस्करी के खिलाफ अब तक की महत्वपूर्ण कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है, जिसमें लगभग 227.7 किलोग्राम कैप्टागन टैबलेट और पाउडर बरामद किया गया है।

इस कार्रवाई के दौरान एक सीरियाई नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कथित रूप से अवैध रूप से भारत में रहकर इस पूरे नेटवर्क को संचालित करने में भूमिका निभा रहा था। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह नेटवर्क केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध मध्य पूर्व और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में सक्रिय अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट से जुड़ा हो सकता है।

गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स'

पर साझा करते हुए एनसीबी की टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य "ड्रग-फ्री इंडिया" बनाना है और इसके लिए हर स्तर पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई 'ऑपरेशन रेजपिल' के तहत की गई, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करना और भारत को ट्रांजिट रूट के रूप में इस्तेमाल होने से रोकना है।

अमित शाह ने अपने संदेश में यह भी कहा कि भारत सरकार उन सभी नेटवर्कों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है जो देश में नशे की तस्करी करते हैं या भारत की जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों में ड्रग सप्लाई के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी संगठित अपराध और आतंकवाद के नेटवर्क को कमजोर करने में मदद करती हैं।

एनसीबी के अधिकारियों के अनुसार, ऑपरेशन रेजपिल एक गोपनीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित अभियान था, जिसमें कई एजेंसियों की सहायता ली गई। इस ऑपरेशन के दौरान मिली जानकारी के आधार पर ड्रग्स की खेप को ट्रैक किया गया और समय रहते उसे जब्त कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि यह खेप मध्य पूर्व के कुछ देशों में भेजी जानी थी, जहां इस तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल कथित तौर पर युद्ध और हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों द्वारा किया जाता है।

कैप्टागन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से सतर्क हैं क्योंकि यह एक ऐसा नशीला पदार्थ माना जाता है जिसका उपयोग केवल नशे के लिए नहीं बल्कि युद्ध और संघर्ष क्षेत्रों में मानसिक और शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए भी किया जाता रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह ड्रग एम्फेटामिन आधारित फेनेथिलिन का एक रूप है, जिसे अक्सर अवैध रूप से तैयार किया जाता है। कैप्टागन के सेवन से व्यक्ति को दर्द, थकान और डर का अहसास कम हो जाता है, जिससे लड़ाई या तनावपूर्ण परिस्थितियों में लंबे समय तक सक्रिय रहने की क्षमता बढ़ जाती है। यही कारण है कि इसे कई बार "जिहादी ड्रग" के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इसका उपयोग कुछ आतंकी संगठनों और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में लड़ाकों द्वारा किया जाता रहा है।

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की ड्रग्स न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं, बल्कि ये अंतरराष्ट्रीय अपराध और आतंक नेटवर्क को भी मजबूत करती हैं। इसके अवैध व्यापार से मिलने वाली रकम का उपयोग कई बार हथियारों की खरीद और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में किया जाता है, जिससे वैश्विक सुरक्षा को खतरा पैदा होता है।

भारत में इस तरह की बड़ी खेप की बरामदगी को एजेंसियां एक महत्वपूर्ण सफलता मान रही हैं। एनसीबी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई केवल एक खेप की जब्ती नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क को समझने और उसे खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जांच अब इस बात पर केंद्रित है कि यह नेटवर्क भारत में कैसे सक्रिय हुआ, इसके स्थानीय सहयोगी कौन हैं और किन अंतरराष्ट्रीय कड़ियों से इसका संबंध जुड़ा हुआ है।

गिरफ्तार किए गए सीरियाई नागरिक से पूछताछ जारी है और एजेंसियां उसके संपर्कों और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही हैं। शुरुआती जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि इस नेटवर्क में कई देशों के लोग शामिल हो सकते हैं, जो ड्रग्स की तस्करी को संगठित तरीके से संचालित कर रहे थे।

सरकार ने इस कार्रवाई को नशे के खिलाफ अपनी नीति की एक बड़ी उपलब्धि बताया है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में इस तरह के अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी और सीमाओं पर निगरानी को और मजबूत किया जाएगा।

फिलहाल जांच जारी है और एनसीबी इस पूरे मामले को एक बड़े ड्रग-टेरर नेटवर्क के रूप में देख रही है। आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और भी अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के कई नए पहलुओं पर रोशनी पड़ सकती है।

संपादकीय

खाड़ी की तपिश से सुलगता तेल, झुलसती जिंदगियां

बृहस्पतिवार को जारी सरकारी आंकड़ों से पता चला कि एक माह के भीतर ही थोक महंगाई दर दुगनी हो गई है। जो कि पिछले 42 महीनों के उच्चतम स्तर पर जा पहुंची है। अब शुक्रवार को पेट्रोल व डीजल तथा सीएनजी के दामों में वृद्धि ने आम आदमी को व्यथित कर दिया। जाहिर है पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि से न केवल यातायात महंगा हो जाता है बल्कि मालभाड़ा बढ़ने से हर चीज के दामों में उछाल आ जाता है। वहीं रोजमर्रा का सामान बनाने वाली कंपनियां दुहाई दे रही हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि से उनकी उत्पादन लागत में दस से बीस फीसदी की वृद्धि हुई है। फलतः इन कंपनियों ने छूट व प्रचार खर्च में कटौती करके भंडारण क्षमता व आपूर्ति शृंखला को मजबूत करना प्राथमिक लक्ष्य बनाया है। अतः देश की एफएमसीजी रोजमर्रा के सामान की लागत बढ़ने व मुनाफे पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिये चरणबद्ध तरीके से वस्तुओं के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। यह भी हकीकत है कि पिछली तिमाही में ये एफएमसीजी पहले ही तीन से पांच प्रतिशत की वृद्धि वस्तुओं की कीमतों में कर चुकी हैं। फलतः आम उपभोक्ता को अभी और महंगाई को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भी एक हकीकत है कि रुपये के गिरते मूल्य ने भी कीमतें बढ़ाने का दबाव बनाया है। कंपनियां अपना मुनाफा बनाये रखने के लिये कीमतें बढ़ाने और पैकेटबंद उत्पादों की मात्रा घटाने की रणनीति पर काम कर रही हैं। आशंका जतायी जा रही है कि पेट्रोल व डीजल के दामों में तीन-तीन रुपये की वृद्धि के बाद टेलीकॉम कंपनियां रिचार्ज प्लान बढ़ा सकती हैं। उनका दावा है कि मोबाइल टॉवर को चलाने में आने वाला 40 फीसदी खर्च सिर्फ पेट्रोल और बिजली पर होता है। यह खर्चा टैरिफ बढ़ाकर ग्राहकों पर डाला जा सकता है। वहीं सरकारी तेल कंपनियां कह रही हैं कि होर्मुज स्ट्रेट बाधित होने से कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के बाद उन्होंने मामूली वृद्धि पेट्रोल व डीजल के दामों में की है।

निश्चित रूप से पश्चिम एशिया संकट के चलते उपजे हालात ने बताया है कि भारत को ऊर्जा सुरक्षा नीति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा ईंधन की खपत को कम करने के आह्वान के कुछ दिन बाद ही पेट्रोल, डीजल व सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी चार साल से अधिक समय में पहली बार की गई है। निस्संदेह, खाड़ी संकट से उपजे हालात में कीमतों में यह वृद्धि अनिवार्य लग रही थी। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के चलते ही सरकार ने यह कदम देर से उठाया है। चुनाव परिणाम आने के बाद जब हैदराबाद में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ईंधन खपत में कटौती करने का आगाह किया था, तो संकेत माना गया कि पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि हो सकती है। सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को हो रहे भारी नुकसान की ओर इशारा करते हुए मूल्य वृद्धि का बचाव किया है। रिपोर्ट बताती है कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र के रिटेलर्स रोजाना एक हजार करोड़ का नुकसान उठा रहे हैं,जबकि कच्चे तेल की कीमत सौ डॉलर प्रति बैरल थी। निस्संदेह, पहले ही मुद्रास्फीति व स्थिर आय से जूझ रहे नागरिकों को सरकार की यह दलील गले नहीं उतरेगी। वैसे भी चुनावी रणनीति के मद्देनजर संचालित आर्थिक निर्णय सार्वजनिक विश्वास में कमी लाते हैं। जाहिर बात है कि करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवार, किसान व छोटे व्यवसाय चलाने वाले लोगों के लिए बढ़ी ईंधन दरें जल्दी ही भोजन, परिवहन और आवश्यक वस्तुओं को महंगा बना देती हैं। फिक्र की बात यह है कि भारत की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता अर्थव्यवस्था को भू राजनीतिक झटकों के प्रति संवेदनशील बना देती है। रूस से मिलने वाला सस्ता कच्चा तेल हमें अस्थायी राहत ही प्रदान करता है। लेकिन यह मार्ग भी प्रतिबंधों, शिपिंग रुकावटों और कूटनीतिक दबावों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। यह संकट भारत को दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति बनाने के लिये बाध्य करता है। हमारी प्राथमिकता सार्वजनिक परिवहन विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग व नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने की होनी चाहिए।

अमेरिका और चीनी की बढ़ती संवाद-प्रक्रिया के रणनीतिक साइड इफेक्ट्स को यूँ समझिए

> "अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्तियाँ हैं। इनके संबंधों का असर लगभग हर देश पर पड़ता है। ऐसे में यदि दोनों के बीच व्यापार, तकनीक, सुरक्षा और कूटनीति पर समझ बढ़ती है, तो वैश्विक तनाव कुछ हद तक कम हो सकता है। साथ ही दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर लाजिमी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हाल में ही बढ़ती संवाद-प्रक्रिया और संभावित रणनीतिक समझौते को दुनिया बेहद गंभीरता से देख रही है, क्योंकि बदलती वैश्विक दुनियादारी और नवमहत्वाकांक्षी देशों-गुटों की मतलबी कूटनीति-अर्थनीति से अमेरिका-चीन दोनों की अंतरराष्ट्रीय बादशाहत खतरे में है। आखिर जब एक तरफ रूस और भारत अपनी दशकों पुरानी मित्रता पर अडिग हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप भी अपने पुराने सम्बन्धों को तरोताजा कर रहे हैं, जो कि अमेरिकी डीप स्टेट की बिल्कुल नई विसात है।देखा जा रहा है कि भारत की चतुराई और रूस की दृढ़ता से अमेरिका अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर तड़फड़ा रहा है। वहीं, रूस-चीन की समझदारी से पश्चिमी एशिया में जो अमेरिका की फजीहत हुई है, उसके बाद अब चीन के समक्ष हथियार डालने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं बचा है। चूंकि ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के फार्मूले पर काम कर रहा हैं और रूस, भारत, फ्रांस, ब्राजील, जापान ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिए हैं, ऐसे में पाकिस्तान को साधकर अरब में अपनी इज्जत बचाना और चीन के दरबार में हाजिरी लगाने के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं बचा हुआ था।

ऐसे में यदि अमेरिका और चीन के बीच टकराव कुछ कम होता है और "नई दोस्ती" या व्यावहारिक सहयोग बढ़ता है, तो इसके वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक प्रभाव दूरगामी हो सकते हैं। चूंकि दोनों देश पहले भी एक दूसरे के करीब रहे हैं, इसलिए उनके बीच कूटनीतिक प्रेम की पहल अमेरिकी की भूल सुधार रणनीति समझी जानी चाहिए और अपने उद्देश्य में ट्रंफ सफल प्रतीत हो चुके हैं। हालांकि यह भविष्य के गर्त में है कि चीनी चाकरी अमेरिका कहाँ तक कर पाएगा?

अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्तियाँ हैं। इनके संबंधों का असर लगभग हर देश पर पड़ता है। ऐसे में यदि दोनों के बीच व्यापार, तकनीक, सुरक्षा और कूटनीति पर समझ बढ़ती है, तो वैश्विक तनाव कुछ हद तक कम हो सकता है। साथ ही दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर लाजिमी है।

पहला, वैश्विक बाजारों में स्थिरताः अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध कम होने पर शेयर बाजारों और निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है। सप्लाई चेन संकट कम हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्र को राहत मिल सकती है।

दूसरा, तेल और ऊर्जा बाजारः यदि दोनों देश सहयोग करते हैं, तो वैश्विक ऊर्जा कीमतों में अनिश्चितता कम हो सकती है। मध्य पूर्व में तनाव कम कराने के लिए संयुक्त दबाव बन सकता है।

तीसरा, डॉलर बनाम युआनः चीन लंबे समय से डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती देना चाहता है। ऐसे में अगर रिश्ते सुधरते हैं, तो अमेरिका कुछ आर्थिक संतुलन के साथ चीन को सीमित छूट दे सकता है, लेकिन डॉलर की केंद्रीय भूमिका तुरंत कमजोर नहीं होगी।

चतुर्थ, रूस, यूरोप और भारत पर प्रभावः जहां तक रूस की बात है कि रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के लिए यह स्थिति मिश्रित हो सकती है। यदि अमेरिका और चीन करीब आते हैं, तो रूस की सामरिक उपयोगिता कुछ घट सकती है। लेकिन चीन रूस को पूरी तरह छोड़ने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि उसे ऊर्जा और सैन्य संतुलन की जरूरत है।

वहीं, जहां तक यूरोप की बात है तो यूरोपीय देश राहत महसूस करेंगे क्योंकि अमेरिका-चीन तनाव से वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा था। लेकिन यूरोप को डर रहेगा कि कहीं अमेरिका चीन के साथ सौदेबाजी में यूरोपीय हितों को पीछे न छोड़ दे। जहां तक भारत की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के लिए यह स्थिति अवसर और चुनौती दोनों ला सकती है। जहां संभावित अवसर के रूप में वैश्विक व्यापार स्थिर होने से भारतीय निर्यात को लाभ मिलेगा। अमेरिका और चीन दोनों भारत को संतुलनकारी शक्ति के रूप में महत्व देते रहेंगे। भारत वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र बन सकता है। जहां तक संभावित चुनौतियाँ की बात है तो यदि अमेरिका चीन के प्रति नरम होता है, तो भारत पर चीन-विरोधी रणनीतिक दबाव कम हो सकता है। सीमा विवादों पर चीन अधिक आत्मविश्वासी रुख भी अपना सकता है। वहीं, क्वाड (QUAD) जैसे समूहों की रणनीतिक धार कुछ कम हो सकती है।

जहां तक सैन्य और सामरिक प्रभाव की बात है तो ताइवान मुद्दे पर तनाव कुछ समय के लिए कम हो सकता है। दक्षिण चीन सागर में सैन्य टकराव की आशंका घट सकती है। लेकिन दोनों महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा पूरी तरह खत्म नहीं होगी। सवाल है कि क्या यह स्थायी दोस्ती होगी? संभवतः नहीं। अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा संरचनात्मक हैः तकनीकी वर्चस्व, सैन्य प्रभुत्व, वैश्विक व्यापार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और इंडो-पैसिफिक रणनीति। इन मुद्दों पर दोनों देशों के हित टकराते रहेंगे। इसलिए यह "पूर्ण मित्रता" से अधिक "व्यावहारिक समझौता" हो सकता है।

इस पुनर्मिलन का सबसे बड़ा वैश्विक संदेश यह है कि दुनिया अब बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहाँ अमेरिका अकेला निर्णायक शक्ति नहीं रहेगा, बल्कि चीन भी खुलकर वैश्विक नेतृत्व चाहता है। वहीं, भारत, रूस, यूरोप, ब्राजील और खाड़ी देश भी अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र मजबूत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ट्रंप-जिनपिंग संवाद वैश्विक शक्ति-संतुलन को नया आकार दे सकता है।

प्रेरणा

भय से मुक्ति का मार्ग

मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, फिर भी मनुष्य पूरे जीवन उससे बचने और उसे भूलने का प्रयास करता रहता है। वह धन, वैभव, पद और सुख-सुविधाओं के पीछे इतना अधिक भागता है कि उसे यह स्मरण ही नहीं रहता कि एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाना है। संसार के अधिकांश संघर्ष, लालच और मोह इसी भ्रम से जन्म लेते हैं कि यह जीवन और इसकी उपलब्धियां स्थायी हैं। लेकिन जैसे ही मृत्यु का विचार सामने आता है, मनुष्य के सारे अभिमान और इच्छाएं क्षणभर में बिखर जाती हैं। इतिहास में अनेक ऐसी घटनाएं मिलती हैं, जिन्होंने मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भोग-विलास नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण है। सम्राट अशोक और उनके छोटे भाई वीतशोक की कथा इसी गहरे सत्य को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रकट करती है। सम्राट अशोक केवल एक विजेता राजा नहीं थे, बल्कि वे गहन चिंतन करने वाले शासक भी थे। कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने लाखों लोगों का रक्तपात देखा, तब उनका अंतर्मन बदल गया। उन्होंने समझ लिया कि तलवार की शक्ति सीमित है और वास्तविक विजय मनुष्य के हृदय को जीतने में है। उसी समय से उनका झुकाव बौद्ध धर्म और श्रमण-भिक्षुओं की ओर बढ़ गया। वे उन संन्यासियों का सम्मान करते थे जिन्होंने संसार के मोह और भय को त्यागकर सत्य की खोज का मार्ग अपनाया था। लेकिन उनके छोटे भाई वीतशोक इस बात को नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि भिक्षु केवल आरामदायक जीवन, स्वादिष्ट भोजन और अच्छे वस्त्र पाने के लिए संन्यास का दिखावा करते हैं। वे त्याग और वैराग्य को कमजोरी समझते थे।

अशोक जानते थे कि केवल तर्क देकर किसी के विचार नहीं बदले जा सकते। जब तक मनुष्य किसी सत्य को स्वयं अनुभव नहीं करता, तब तक वह उसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए उन्होंने अपने भाई को जीवन का वास्तविक अर्थ समझाने के लिए एक अनोखी योजना बनाई। एक दिन मंत्रियों ने वीतशोक से कहा कि सम्राट के बाद वही राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। इसलिए उन्हें राजसी वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठना चाहिए ताकि देखा जा सके कि वे राजा के रूप में कैसे लगते हैं। यह सुनकर वीतशोक अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुंदर वस्त्र धारण किए, बहुमूल्य आभूषण पहने और गर्व से सिंहासन पर जाकर बैठ गए। उस क्षण उन्हें लगा कि संसार का सबसे बड़ा सुख उन्हें प्राप्त हो गया है।

तभी सम्राट अशोक वहां पहुंचे। उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि उनके रहते सिंहासन पर बैठना राजद्रोह है और इस अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सुनते ही वीतशोक भय से कांप उठे। कुछ ही क्षण पहले जो व्यक्ति गर्व और आनंद में डूबा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया। मंत्रियों ने बहुत विनती की, तब अशोक ने कहा कि चूंकि वह उनके प्रिय भाई हैं, इसलिए उन्हें दंड से पहले एक सप्ताह तक राजसी सुख भोगने का अवसर दिया जाएगा। अब वीतशोक सात दिनों के लिए राजा बन गए। महल की सारी सुविधाएं उनके सामने थीं। स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र, सेवकों की भीड़ और अपार ऐश्वर्य उनके चारों ओर था। लेकिन उनके पीछे हर समय दो सैनिक नंगी तलवारें लिए चलते रहते थे। वे सैनिक उन्हें हर पल यह याद दिलाते रहते कि सात दिन बाद मृत्यु निश्चित है। यही विचार उनके मन पर इतना भारी हो गया कि वे किसी भी सुख का आनंद नहीं ले सके। न उन्हें भोजन में स्वाद आया, न संगीत अच्छा लगा और न ही राजसी वैभव आकर्षित कर सका। रातों को उन्हें नींद नहीं आती थी। हर क्षण उनके मन में केवल एक ही विचार घूमता रहता कि मृत्यु निकट है।

सात दिन बाद उन्हें सम्राट अशोक के सामने प्रस्तुत किया गया। अशोक ने मुस्कराकर पूछा कि राजपद का सुख कैसा लगा। वीतशोक ने अत्यंत दुखी स्वर में कहा कि जहां हर समय मृत्यु सामने खड़ी हो, वहां सुख और ऐश्वर्य का कोई महत्व नहीं रह जाता। जिस व्यक्ति को यह पता हो कि उसका अंत निकट है, वह भला भोग-विलास में आनंद कैसे ले सकता है।

तब अशोक ने उन्हें जीवन का गहरा रहस्य समझाया। उन्होंने कहा कि तुम केवल एक निश्चित मृत्यु के भय से ही सुखों का उपभोग नहीं कर सके, जबकि श्रमण-भिक्षु तो जन्म-जन्मांतर के मृत्यु-भय से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। वे भोजन और वस्त्र के लालच में संन्यासी नहीं बने हैं। वे उन तुच्छ इच्छाओं से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उनका उद्देश्य उस भय को समाप्त करना है जो मनुष्य को जन्म से मृत्यु तक बांधे रखता है।

यह कथा केवल अतीत की एक घटना नहीं है, बल्कि आज के समाज का भी दर्पण है। आज का मनुष्य भी बाहरी सुखों में ही जीवन का अर्थ खोज रहा है। वह अधिक धन कमाने, बड़ा घर बनाने और ऊंचा पद पाने के लिए दिन-रात संघर्ष करता है। लेकिन भीतर कहीं न कहीं मृत्यु का भय उसे लगातार परेशान करता रहता है। कोई बीमारी से डरता है, कोई भविष्य से, कोई अपनों को खोने से और कोई अकेलेपन से भयभीत रहता है। बाहर से सफल दिखाई देने वाला व्यक्ति भी भीतर से असुरक्षित हो सकता है। आधुनिक जीवन में सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन मानसिक शांति घटती जा रही है। इसका कारण यही है कि मनुष्य ने जीवन के बाहरी पक्ष को ही सब कुछ मान लिया है। वह भूल गया है कि संसार का हर सुख अस्थायी है। मृत्यु का स्मरण यदि सही दृष्टि से किया जाए तो वह निराशा नहीं, बल्कि जागृति का कारण बन सकता है। यह मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है और उसे यह सिखाता है कि समय सीमित है, इसलिए जीवन को सार्थक बनाना चाहिए।

भारतीय दर्शन में मृत्यु को अंत नहीं माना गया, बल्कि परिवर्तन माना गया है। आत्मा को अमर बताया गया है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों और संतों ने हमेशा आत्मबोध और वैराग्य पर जोर दिया। उनका उद्देश्य मनुष्य को संसार से भागना नहीं, बल्कि उसके वास्तविक स्वरूप को समझाना था। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है, तब उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। वह संग्रह और भोग की अंधी दौड़ से बाहर निकलकर सत्य और करुणा की ओर बढ़ता है। सम्राट अशोक ने अपने भाई को उपदेश नहीं दिया, बल्कि अनुभव के माध्यम से सत्य का बोध कराया। यही इस कथा की सबसे बड़ी विशेषता है। कई बार जीवन के गहरे सत्य शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभवों से समझ आते हैं। मृत्यु का भय मनुष्य को तोड़ भी सकता है और उसे जागृत भी कर सकता है। जो व्यक्ति इस भय में डूब जाता है, वह जीवनभर अशांत रहता है। लेकिन जो इसे समझकर आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है।

सच्चा सुख बाहरी ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि उस मानसिक अवस्था में है जहां मृत्यु का भय मनुष्य को विचलित न कर सके। जिसने जीवन की अस्थिरता को समझ लिया, वही वास्तव में स्वतंत्र है। वही संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ सकता है। यही इस कथा का गहरा संदेश है कि मृत्यु से डरकर नहीं, बल्कि उसे समझकर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है।

Mussoorie की जगह Bangladesh को भाने लगा Lahore, भारत की बजाय पाक में अपने अफसरों को ट्रेनिंग दिला रहे हैं Tarique Rahman

बांग्लादेश में नई सरकार आने के बाद लगा था कि मुहम्मद युनूस वाली गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी और चीन तथा पाकिस्तान के खेमे में जाने की बजाय ढाका का झुकाव भारत की ओर ही रहेगा लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। हम आपको बता दें कि ताजा घटनाक्रम के तहत बांग्लादेश ने अपने नौकरशाहों के प्रशिक्षण के लिए भारत के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की बजाय पाकिस्तान के लाहौर स्थित सिविल सर्विसेज अकादमी को चुना है। यह कदम दक्षिण एशिया की बदलती कूटनीतिक राजनीति और बांग्लादेश की नई विदेश नीति का संकेत माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि करीब एक दशक तक बांग्लादेशी अधिकारियों के लिए मसूरी प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र रहा। वर्ष 2014 में शेख हसीना सरकार के दौरान बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय और भारत के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के बीच समझौता हुआ था। इसके बाद 2019 और 2024 में भी नए समझौते हुए। 2019 से 2024 के बीच भारत में 1019 से अधिक बांग्लादेशी सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि कुल मिलाकर लगभग 2500 अधिकारी भारत में प्रशिक्षित हुए। लेकिन अब पहली बार 12 बांग्लादेशी अधिकारी 4 से 21 मई तक लाहौर में प्रशिक्षण ले रहे हैं और इसका पूरा खर्च पाकिस्तान सरकार उठा रही है।

यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद ढाका और इस्लामाबाद के बीच रिश्ते तेजी से मजबूत हो रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबायद इस्लाम और पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री सैयद मोहसिन रजा नकवी के बीच हुई बैठक में दोनों देशों ने व्यापार, खेल, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और डिजिटल नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को फिर से सक्रिय बनाने और क्षेत्रीय संपर्क मजबूत करने की आवश्यकता भी दोहराई।

विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश अब अपनी विदेश नीति में अधिक रणनीतिक स्वतंत्रता दिखाना चाहता है। नई राजनीतिक व्यवस्था के बाद ढाका भारत पर अत्यधिक निर्भरता से बचते हुए पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के साथ भी संतुलित संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि नई सरकार भारत के साथ संबंध बनाए रखते हुए दूसरे विकल्पों की ओर भी बढ़ रही है। हालांकि बांग्लादेश और भारत दोनों यह समझते हैं कि टकराव लंबे समय तक उनके हित में नहीं है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, आर्थिक संपर्क और राजनयिक संवाद फिर से शुरू करने की कोशिशें भी हो रही हैं।

फिर भी दोनों देशों के बीच अविश्वास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। शेख हसीना का भारत में रहना बांग्लादेश की राजनीति में लगातार विवाद का विषय बना हुआ है। ढाका में यह धारणा मजबूत हुई है कि भारत बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में जरूरत से ज्यादा प्रभाव बनाए रखना चाहता है। खासकर युवा वर्ग में राष्ट्रवाद और राजनीतिक स्वायत्तता की भावना पहले से अधिक मजबूत हुई है। भारत विरोधी भावना अब केवल वैचारिक मुद्दा नहीं रह गई, बल्कि घरेलू राजनीतिक पहचान का हिस्सा बनती जा रही है।

सीमा प्रबंधन, अवैध तस्करी, प्रवासन और जल बंटवारे जैसे पुराने विवाद भी अब तक हल नहीं हो पाए हैं। तीस्ता जल समझौता वर्षों से लंबित है और जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में यह विवाद और गंभीर हो सकता है। हालांकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुए बदलाव के बाद कुछ विश्लेषकों को उम्मीद है कि इस दिशा में नई पहल संभव हो सकती है। इसके बावजूद आर्थिक संबंध दोनों देशों के रिश्तों को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारतीय बाजार और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर है, जबकि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बांग्लादेश का भूभाग संपर्क और व्यापार के लिहाज से बेहद अहम है। यही आर्थिक परस्पर निर्भरता हर तनाव के बावजूद रिश्तों को पूरी तरह टूटने से बचाती रही है।

इसी बीच, चीन भी बांग्लादेश की विदेश नीति में तेजी से प्रभाव बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान अपनी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा चीन को समर्पित कर सकते हैं। चीन पहले ही बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचा हुआ बता चुका है। इससे साफ संकेत मिलता है कि ढाका अब बहुध्रुवीय कूटनीति अपनाते हुए भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है।

देखा जाये तो दक्षिण एशिया की बदलती राजनीति में बांग्लादेश का यह नया रुख केवल एक देश की विदेश नीति का बदलाव नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन के नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत और बांग्लादेश अपने ऐतिहासिक रिश्तों को नई राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ किस तरह संतुलित करते हैं।

बहरहाल, विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का सबसे मजबूत पक्ष यह रहा है कि भारत ने तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव और तनाव के बावजूद बांग्लादेश के साथ संवाद और सहयोग के रास्ते कभी पूरी तरह बंद नहीं किये। चाहे ऊर्जा सहयोग हो, व्यापार, संपर्क परियोजनाएं, सुरक्षा साझेदारी या मानवीय सहायता, भारत ने हर कठिन समय में ढाका का साथ दिया है। दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान की नीतियों को दक्षिण एशिया में अक्सर रणनीतिक हितों और अवसरवाद से प्रेरित माना जाता रहा है। चीन निवेश और बुनियादी ढांचे के जरिये प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता है, जबकि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्तों का इतिहास भी कई संवेदनशील अध्यायों से जुड़ा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में बांग्लादेश को यह एहसास हो सकता है कि स्थायी, भरोसेमंद और निस्वार्थ सहयोगी के रूप में भारत का महत्व सबसे अधिक है।

अभियान

अखंड सौभाग्य और आस्था का प्रतीक है वट सावित्री व्रत

भारतीय संस्कृति में व्रत और त्योहार केवल धार्मिक परंपराएं नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के गहरे आध्यात्मिक, सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों को भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं द्वारा रखे जाने वाले व्रतों में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु, परिवार की सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है। हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को महिलाएं श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान कर सुंदर वस्त्र धारण करती हैं, व्रत रखती हैं और बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा करती हैं। पूजा के दौरान महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर धागा लपेटती हैं, जल अर्पित करती हैं और सावित्री-सत्यवान की कथा सुनती हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी भारतीय समाज में उसी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है।

वट सावित्री व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण, निष्ठा और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत के पीछे जो कथा जुड़ी हुई है, वह भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति और दृढ़ संकल्प का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। मान्यता है कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर यह सिद्ध कर दिया था कि सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास किसी भी कठिन परिस्थिति को बदल सकता है। यही कारण है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं सावित्री को आदर्श मानकर अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस वर्ष 16 मई 2026 को वट सावित्री व्रत रखा जा रहा है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 07 बजकर 12 मिनट से 08 बजकर 24 मिनट तक बताया गया है। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 50 मिनट से दोपहर 12 बजकर 45 मिनट तक रहेगा। इस दौरान पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। महिलाएं प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और सुहाग की सभी सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनती हैं। इसके बाद वे वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करती हैं। पेड़ की जड़ में जल, रोली, अक्षत, फूल और मिठाई अर्पित की जाती है। फिर महिलाएं पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र तथा सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करती हैं।

बरगद के पेड़ को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और दिव्य माना गया है। इसे वट वृक्ष भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। कहा जाता है कि इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसी कारण यह वृक्ष सृष्टि, पालन और संहार तीनों शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। बरगद का पेड़ लंबे समय तक हरा-भरा और मजबूत बना रहता है। इसकी शाखाएं लगातार फैलती रहती हैं और इसकी जड़ें धरती को मजबूती से पकड़कर इसे स्थिर बनाए रखती हैं। यही कारण है कि इसे दीर्घायु, स्थिरता, अखंड सौभाग्य और मजबूत रिश्तों का प्रतीक माना गया है।

भारतीय संस्कृति में पेड़ों को केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं माना गया, बल्कि उन्हें देवतुल्य स्थान दिया गया है। पीपल, तुलसी, नीम और बरगद जैसे वृक्षों की पूजा करने की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। इसके पीछे धार्मिक महत्व के साथ-साथ वैज्ञानिक कारण भी छिपे हैं। बरगद का वृक्ष अत्यधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ माना जाता है। इसकी विशाल छाया गर्मी से राहत देती है और यह पर्यावरण को शुद्ध रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गांवों में बरगद के पेड़ के नीचे पंचायतें लगती थीं, यात्री विश्राम करते थे और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। इस प्रकार यह वृक्ष सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।

वट सावित्री व्रत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी कथा है, जो भारतीय नारी के साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। कथा के अनुसार राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी थी। जब उसके विवाह की बात आई तो उसने स्वयं सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। लेकिन ऋषियों ने बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के एक वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर भी सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। उसने सत्यवान से विवाह किया और पूरी निष्ठा से अपने वैवाहिक जीवन का पालन करने लगी।

जब सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आया तो सावित्री ने कठोर व्रत और तपस्या शुरू कर दी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, उस दिन वह उनके साथ जंगल गई। जंगल में लकड़ी काटते समय सत्यवान अचानक बेहोश होकर बरगद के पेड़ के नीचे गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। तभी यमराज वहां आए और सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे कई बार लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और निष्ठा के कारण पीछे नहीं हटी।

सावित्री की बुद्धिमानी, साहस और समर्पण से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास-ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने यह वरदान दे दिया। इसके बाद उसने अपने पिता के लिए सौ पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने वह भी स्वीकार कर लिया। अंत में सावित्री ने अपने लिए भी सौ पुत्रों का वरदान मांग लिया। तब यमराज समझ गए कि बिना पति के यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। सावित्री की चतुराई और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। तभी से यह व्रत पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाने लगा।

वट सावित्री व्रत भारतीय समाज में केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह वैवाहिक संबंधों की मजबूती और पारिवारिक मूल्यों का भी प्रतीक है। यह व्रत पति-पत्नी के बीच विश्वास, प्रेम और समर्पण की भावना को मजबूत करता है। आज के आधुनिक समय में जहां रिश्तों में धैर्य और समझ की कमी देखने को मिलती है, वहां यह व्रत परिवार और वैवाहिक जीवन के महत्व की याद दिलाता है। हालांकि समय के साथ समाज और जीवनशैली में कई बदलाव आए हैं, लेकिन वट सावित्री व्रत की आस्था आज भी वैसी ही बनी हुई है। शहरों से लेकर गांवों तक महिलाएं पूरे श्रद्धाभाव से यह व्रत रखती हैं। कई स्थानों पर महिलाएं सामूहिक रूप से वट वृक्ष के पास एकत्र होकर पूजा करती हैं और सावित्री-सत्यवान की कथा सुनती हैं। इससे सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं को भी मजबूती मिलती है।

इस व्रत का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, सच्चा विश्वास और दृढ़ निश्चय हर संकट को दूर कर सकता है। सावित्री ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि शक्ति भी है। उनका चरित्र भारतीय नारी के साहस, बुद्धिमत्ता और समर्पण का प्रतीक बन गया है।

बरगद का वृक्ष भी इस व्रत के माध्यम से केवल एक पेड़ नहीं रह जाता, बल्कि वह जीवन, स्थिरता और अमरता का प्रतीक बन जाता है। उसकी विशाल जड़ें यह संदेश देती हैं कि परिवार और रिश्तों की नींव जितनी मजबूत होगी, जीवन उतना ही स्थिर और सुखी रहेगा। उसकी फैली हुई शाखाएं समृद्धि और संरक्षण का प्रतीक मानी जाती हैं।

वट सावित्री व्रत भारतीय संस्कृति की उस गहरी परंपरा को दर्शाता है, जहां प्रकृति, धर्म और पारिवारिक जीवन एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, विश्वास और जीवन मूल्यों का उत्सव है। यही कारण है कि सदियों बाद भी इसकी महिमा और महत्व आज भी लोगों के मन में उतना ही गहरा बना हुआ है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

नशे में बेकाबू सिपाही ने इंसास राइफल तान कमांडर को दौड़ाया, मेरठ पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस विभाग के भीतर अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। विजिलेंस कार्यालय में तैनात पुलिस गारद में उस समय अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया, जब एक सिपाही ने शराब के नशे में अपनी इंसास राइफल लोड कर अपने ही गारद कमांडर पर तान दी। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि जान बचाने के लिए कमांडर को मौके से भागना पड़ा, जबकि आरोपी सिपाही करीब 200 मीटर तक राइफल लेकर उनका पीछा करता रहा और गोली मारने की धमकी देता रहा। इस पूरी घटना ने पुलिस लाइन से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक हलचल मचा दी।

बताया जा रहा है कि मामला मेरठ पुलिस लाइन से विजिलेंस कार्यालय में तैनात पुलिस गारद का है। यहां हेड कांस्टेबल अनिल कुमार गारद कमांडर के रूप में तैनात हैं, जबकि सिपाही हेमंत कुमार उनके अधीन कार्यरत था। हाल ही में गारद कमांडर अनिल कुमार ने ड्यूटी व्यवस्था को सख्त करते हुए एक आदेश जारी किया था, जिसमें ड्यूटी के दौरान बिना अनुमति गारद छोड़ने पर रोक लगाई गई थी। सूत्रों के अनुसार आरोपी सिपाही हेमंत इस आदेश से नाराज चल रहा था और इसी बात को लेकर उसके मन में कमांडर के प्रति आक्रोश बढ़ गया था।

शुक्रवार रात यह नाराजगी खतरनाक रूप में सामने आई। आरोप है कि हेमंत कुमार ने शराब पी रखी थी और नशे की हालत में उसने सरकारी इंसास राइफल उठाई। इसके बाद उसने राइफल में गोलियां भरीं और सीधे अपने कमांडर अनिल कुमार के सामने पहुंच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी सिपाही बेहद आक्रामक स्थिति में था और उसने कमांडर पर राइफल तानते हुए धमकी देना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी घबरा गए।

स्थिति को गंभीर होता देख गारद कमांडर अनिल कुमार ने खुद को बचाने के लिए वहां से भागना शुरू किया। लेकिन आरोपी सिपाही हेमंत राइफल लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। बताया जा रहा है कि करीब 200 मीटर तक उसने सड़क पर कमांडर का पीछा किया और लगातार गोली मारने

की धमकी देता रहा। बीच सड़क पर एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी को हथियार लेकर दौड़ते देख आसपास के लोग भी सहम गए। इलाके में अफरा-तफरी मच गई और कुछ ही देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना तुरंत पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई गई। आरआई हरपाल सिंह के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया और आरोपी सिपाही को हिरासत में लिया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया गया कि उसके पास मौजूद सरकारी हथियार सुरक्षित तरीके से जब्त कर लिया जाए।

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय ने तत्काल जांच के आदेश दिए। मामले की जांच सीओ सिविल लाइंस शुचिता सिंह को सौंपी गई। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि आरोपी सिपाही ने वास्तव में सरकारी हथियार का दुरुपयोग किया और शराब के नशे में अपने वरिष्ठ अधिकारी को जान से मारने की धमकी दी। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद आरोपी सिपाही हेमंत कुमार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सरकारी ड्यूटी के दौरान सरकारी असलाह के दुरुपयोग, जान से मारने की नीयत से पीछा करने और विभागीय अनुशासन तोड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों का कहना है कि यह केवल अनुशासनहीनता का मामला नहीं, बल्कि पुलिस बल की आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर मामला है। यदि समय रहते स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया जाता, तो कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी।

एसएसपी अविनाश पांडेय ने आरोपी सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। मेडिकल परीक्षण में शराब सेवन की पुष्टि होने के बाद विभाग ने उसके खिलाफ अतिरिक्त कार्रवाई करते हुए आधा वेतन रोकने का निर्णय भी लिया है। अधिकारियों का कहना है कि विभागीय जांच के आधार पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

इस घटना ने पुलिस विभाग के भीतर अनुशासन और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि हथियारबंद बलों में कार्यरत कर्मचारियों की मानसिक स्थिति, तनाव और व्यवहार की समय-समय पर निगरानी बेहद जरूरी है। लंबे समय तक तनावपूर्ण ड्यूटी, अनुशासनात्मक दबाव और व्यक्तिगत समस्याएं कई बार कर्मचारियों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। हालांकि इस मामले में शराब का सेवन और सरकारी हथियार का दुरुपयोग स्थिति को और अधिक गंभीर बना देता है।

पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों का कहना है कि किसी भी सशस्त्र बल में हथियार अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई जवान नशे की हालत में हथियार का इस्तेमाल करता है, तो वह न केवल अपने सहयोगियों बल्कि आम जनता के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। यही कारण है कि ऐसे मामलों में विभाग आमतौर पर बेहद सख्त कार्रवाई करता है।

घटना के बाद विजिलेंस कार्यालय और पुलिस लाइन में सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा शुरू कर दी गई है। यह जांच की जा रही है कि आरोपी सिपाही शराब के नशे में होने के बावजूद हथियार तक कैसे पहुंचा और ड्यूटी के दौरान उसकी गतिविधियों पर निगरानी क्यों नहीं रखी जा सकी। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि सुरक्षा प्रोटोकॉल में किसी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर अन्य जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

मेरठ की यह घटना सोशल मीडिया और पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बनी हुई है। आम लोगों के बीच भी इसे लेकर चिंता देखी जा रही है कि जिन पुलिसकर्मियों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, यदि वे स्वयं इस तरह की हरकतों में शामिल हों तो यह गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि विभाग में अनुशासनहीनता और हथियारों के दुरुपयोग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

फिलहाल आरोपी सिपाही के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच जारी है। विभागीय जांच रिपोर्ट आने के बाद उसके खिलाफ और कठोर कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस अधिकारी पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

स्कूल लौटते कदमों से बदलेगा भविष्य : सूरत में ड्रॉपआउट बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का अभियान तेज

सूरत। आधुनिकता और औद्योगिक विकास की तेज रफ्तार के बीच सूरत शहर में शिक्षा से दूर हो रहे बच्चों को फिर से स्कूलों तक पहुंचाने की दिशा में सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहल शुरू की है। शहर के विभिन्न इलाकों में स्कूल छोड़ चुके बच्चों की पहचान कर उन्हें दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नगर निगम द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य केवल बच्चों का स्कूल में प्रवेश कराना नहीं, बल्कि उनके भविष्य को फिर से उज्ज्वल दिशा देना भी है।

म्युनिसिपल कमिश्नर के निर्देश पर सेंट्रल ज़ोन क्षेत्र में अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग की टीम और स्कूल स्टाफ ने कई बस्तियों एवं श्रमिक इलाकों का दौरा कर ड्रॉपआउट बच्चों और उनके अभिभावकों से सीधे संवाद किया। अभियान के दौरान अधिकारियों ने कादर शाह नाल, छप्पन्न चाल और रुदरपुरा जैसे क्षेत्रों में घर-घर पहुंचकर उन बच्चों की जानकारी जुटाई जो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुके हैं। कई परिवार आर्थिक कठिनाइयों, कामकाज की मजबूरियों और जागरूकता की कमी

के कारण बच्चों की पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे थे। ऐसे परिवारों को अधिकारियों ने समझाया कि शिक्षा ही बच्चों के बेहतर भविष्य और सामाजिक विकास का सबसे मजबूत आधार है।

अभियान के दौरान अधिकारियों ने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने, पढ़ाई में रुचि लेने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। वहीं अभिभावकों को भी यह बताया गया कि शुरुआती शिक्षा से दूर होने वाले बच्चे भविष्य में कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। नगर निगम की टीम ने अभिभावकों को सरकारी स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं, मुफ्त शिक्षा, पुस्तकें, यूनिफॉर्म और अन्य योजनाओं की जानकारी देते हुए बच्चों को दोबारा स्कूल भेजने की अपील की।

इस विशेष अभियान में डॉ. प्रदीप उमरीगर (मेडीकल हेल्थ ऑफिसर, एसएमसी), डॉ. फेनिल पटेल, डॉ. अमित पटेल (डिप्टी हेल्थ ऑफिसर, सेंट्रल ज़ोन), रमेशभाई पटेल (URC, रांदेर सेंट्रल ज़ोन), हर्षिलाबेन (CRC CO) सहित स्कूल नंबर-18 और स्कूल नंबर-28 के प्रिंसिपल एवं स्टाफ सक्रिय रूप से शामिल रहे। टीम ने न केवल बच्चों की स्थिति का आकलन किया बल्कि जरूरत पड़ने पर उन्हें स्कूल में पुनः प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू की।

नगर निगम अधिकारियों का मानना है कि शहर के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व भी है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच मजदूर और निम्न आय वर्ग के परिवारों के बच्चों का पढ़ाई से दूर होना एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में यह अभियान उन बच्चों के जीवन में नई उम्मीद जगाने का काम कर रहा है जो किसी कारणवश स्कूल छोड़ चुके हैं। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि इस पहल से अधिक से अधिक बच्चे दोबारा स्कूलों में प्रवेश लेकर अपनी अधूरी पढ़ाई शुरू करेंगे और शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को नई दिशा देंगे। नगर निगम का यह प्रयास शहर में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ यह संदेश भी दे रहा है कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे।

साइबर अपराधों में चिंताजनक वृद्धि हो रही है, जागरूकता की कमी के कारण लोग धोखाधडी का शिकार बन रहे हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। आज के दौर में, डिजिटलीकरण की वैसी कोई "पूर्ण सुरक्षा" नहीं है जैसी हम चाहते हैं, और जिसे सुरक्षित बताया जाता है वह भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। परिणामस्वरूप, देश में न केवल वित्तीय लेन-देन बल्कि विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध भी हो रहे हैं। और यह दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं, सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए बनाया गया साइबर सिस्टम पूरी तरह से निष्फल साबित हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि साइबर सिस्टम भी बढ़ते अपराधों से निपटने में बहुत सीमित साबित हो रहा है। यहां तक कि शिक्षित लोग भी ऐसे अपराधों के प्रति जागरूकता नहीं दिखाते और साइबर अपराध का शिकार होकर पुलिस के पास जाते हैं। इसका कारण यह है कि जनता को जानकारी नहीं है या वे जागरूक नहीं हैं। इसी वजह से साइबर अपराधों की संख्या बढ़ रही है, जिसे सिस्टम रोकने में सक्षम नहीं है। इतना ही नहीं, कई मामलों में साइबर अपराधी साइबर अपराधों को रोकने वाले सरकारी सिस्टम से कहीं आगे और चालाक साबित हो रहे हैं। डिजिटल गिरफ्तारी से लेकर तरह-तरह

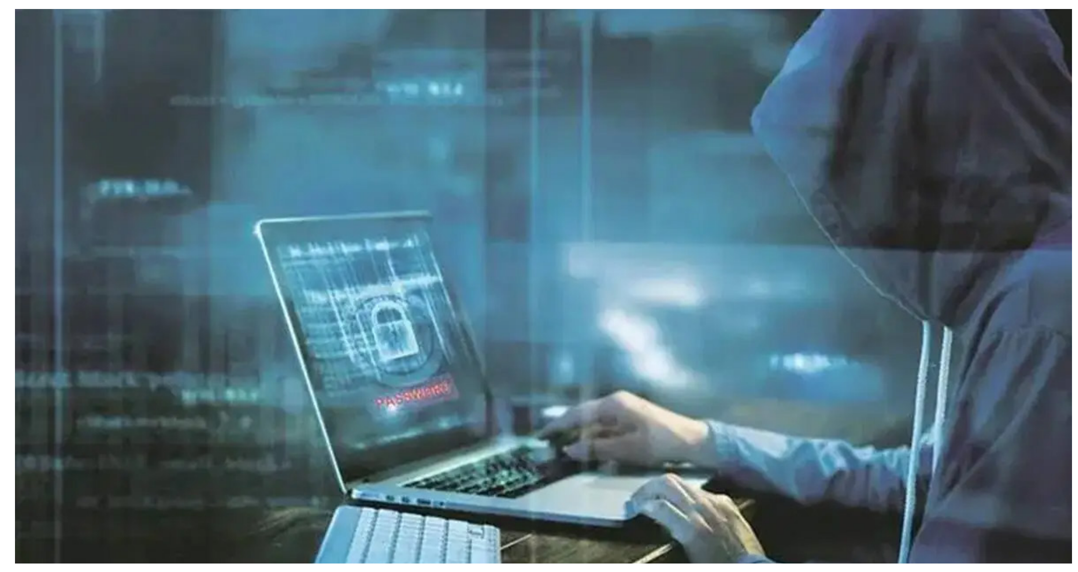

के हथकंडों तक, ग्राहकों के खातों से लाखों रुपये पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं और फिर उनका कोई सुराग नहीं मिलता। एक ओर, कड़े उपायों और जागरूकता के दावों के बावजूद, क्या साइबर धोखाधड़ी रुक नहीं रही बल्कि बढ़ रही है? देश भर में हर साल लाखों छोटी-बड़ी साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज होती हैं। एक व्यक्ति को अपनी जीवन भर की मेहनत से कमाई गई रकम पल भर में गंवानी पड़ती है। आज के समय में, साइबर अपराधी हर साल करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी कर रहे हैं और जांच एजेंसियां उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। नतीजतन, अपराधी नागरिकों को किसी न किसी रूप में लुभाकर या धमकाकर अपना शिकार बनाते रहते हैं। परिणामस्वरूप, पिछले साल 22,845 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी हुई। जबकि वर्ष 2023 में यह आंकड़ा मात्र 7,465 करोड़ रुपये था। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री द्वारा दी गई इस जानकारी ने चिंता को और बढ़ा दिया है। इन आंकड़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि पुलिस व्यवस्था साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने में विफल रही है। अंततः, आम नागरिकों में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है और उन्हें शिक्षित करने की भी उतनी ही आवश्यकता है।

"कांग्रेस मुक्त" अभियान का मतलब वंशवाद और नक्सलवाद से मुक्ति : स्वतंत्रदेव सिंह

कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश की राजनीति और शासन व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला है। उन्होंने दावा किया कि आज देश वंशवाद, नक्सलवाद और माओवाद जैसी विचारधाराओं से तेजी से मुक्त हो रहा है और भाजपा का "कांग्रेस मुक्त भारत" अभियान वास्तव में देश को परिवारवाद और हिंसक विचारधाराओं से मुक्त करने का अभियान है।

कानपुर में भाजपा ग्रामीण इकाई के दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे स्वतंत्रदेव सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि विचारधारा आधारित संगठन है, जिसने देश की राजनीति की दिशा बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले देश की राजनीति परिवारों और वंशवाद के इर्द-गिर्द घूमती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीति में सामान्य कार्यकर्ता और आम जनता की भागीदारी बढ़ी है।

स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नक्सलवाद और माओवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। उन्होंने दावा किया कि जिन क्षेत्रों में कभी नक्सली हिंसा का आतंक था, वहां अब विकास और लोकतंत्र की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की योजनाओं के जरिए सरकार ने उन इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों ने देश में सुरक्षा और विकास दोनों को मजबूती दी है।

उन्होंने कहा कि भाजपा का "कांग्रेस मुक्त" अभियान किसी व्यक्ति या दल के खिलाफ नहीं, बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ है जिसने दशकों तक देश में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यहां किसी परिवार विशेष का वर्चस्व नहीं है। पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता भी मेहनत और समर्पण के दम पर बड़े पद तक पहुंच

सकता है।

कैबिनेट मंत्री ने भाजपा संगठन की संरचना और कार्यपद्धति पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी में कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा संगठन को प्राथमिकता दी है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि देश में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने सामान्य कार्यकर्ता के रूप में राजनीति शुरू की और आज महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।

प्रशिक्षण वर्ग को संगठनात्मक मजबूती का माध्यम बताते हुए स्वतंत्रदेव सिंह ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव तक पहुंचकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीब, किसान, युवा, महिला और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की सही जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि आज देश के अधिकांश राज्यों में भाजपा या भाजपा समर्थित सरकारें हैं और जनता का विश्वास लगातार पार्टी के साथ बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वहां भी भाजपा ने अपनी राजनीतिक ताकत को मजबूत किया है और जनता परिवर्तन चाहती है। उनके अनुसार भाजपा का विस्तार केवल चुनावी सफलता नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और संगठन की मेहनत का परिणाम है।

स्वतंत्रदेव सिंह ने कार्यकर्ताओं से अनुशासन, समर्पण और निरंतर जनसंपर्क बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम के दौरान भाजपा ग्रामीण इकाई के कई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशिक्षण वर्ग में संगठनात्मक रणनीति, बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क अभियान और सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार को लेकर भी चर्चा की गई। भाजपा नेताओं ने इसे आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण बताया।

कानपुर में आयोजित यह प्रशिक्षण वर्ग भाजपा के संगठनात्मक विस्तार और कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व लगातार बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने पर जोर दे रहा है, ताकि आगामी चुनावों में पार्टी की पकड़ और मजबूत हो सके। स्वतंत्रदेव सिंह के संबोधन ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के साथ-साथ भाजपा की राजनीतिक और वैचारिक दिशा को भी स्पष्ट रूप से सामने रखा।

कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 की बढ़ोतरी हुई है, वहीं सीएनजी की कीमत में भी 2 की वृद्धि हुई है

छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का असर आखिरकार भारत पर भी दिखने लगा है। शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, यह बढ़ोतरी मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण हुई है। विपक्षी दलों ने पहले ही आशंका जताई थी कि पांच राज्यों में चुनाव खत्म होते ही मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा देगी। हालांकि, सरकार ने उस समय इन दावों को खारिज कर दिया था। चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए गए थे। आज, 15 मई को, सरकार ने आखिरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इस कदम से महंगाई बढ़ने की आशंका है। दिल्ली में नई दरों के अनुसार, पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 87.67 रुपये से बढ़कर 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इस बढ़ोतरी के साथ, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के करीब पहुंच गई है।

सीएनजी की कीमत में 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई

दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी की कीमत अब 77.09 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 79.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। एक दिन पहले मुंबई में भी सीएनजी की कीमत में 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में सीएनजी की कीमत अब 84 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगी। सरकार का कहना है कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और मध्य पूर्व में बिगड़ती स्थिति के बावजूद भारत ने अब तक खुदरा ईंधन की कीमतों में बड़ी वृद्धि करने से परहेज किया है। हालांकि, बढ़ते दबाव के जवाब में अब यह कदम उठाया गया है।

आय से अधिक संपत्ति पर शिकंजा : कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के चार ठिकानों पर ईओयू की बड़ी रेड

पटना। बिहार में भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। पटना और जमुई में हुई इस कार्रवाई से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया। ईओयू की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि अभियंता ने अपनी वैध आय से लगभग 81.5 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की है। जांच एजेंसी के अनुसार गोपाल कुमार के पास करीब 2 करोड़ 61 हजार रुपये की ऐसी संपत्ति पाई गई है, जिसका स्पष्ट और वैध स्रोत अब तक सामने नहीं आया है।

आर्थिक अपराध इकाई द्वारा लंबे समय से गोपाल कुमार की संपत्तियों और वित्तीय गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही थी। जांच एजेंसी को सूचना मिली थी कि अभियंता ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सेवा अवधि के दौरान भारी मात्रा में चल और अचल संपत्ति अर्जित की है। इसके बाद ईओयू ने गुप्त रूप से उनके बैंक खातों, निवेश, जमीन खरीद, आवासीय संपत्तियों और अन्य वित्तीय लेन-देन की जांच शुरू की। प्रारंभिक सत्यापन में आय और संपत्ति के बीच बड़ा अंतर सामने आने के बाद ईओयू ने मामला दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी।

ईओयू ने थाना कांड संख्या-08/26 दिनांक 15 मई 2026 दर्ज करते हुए ग्रामीण कार्य प्रमंडल झाझा (जमुई) में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार को आरोपी बनाया। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान अभियंता की आय, वेतन, वैध निवेश और अन्य वित्तीय स्रोतों का आकलन किया गया। इसके मुकाबले जो संपत्ति सामने आई, वह उनकी ज्ञात आय से काफी अधिक पाई गई। यही कारण है कि ईओयू ने विशेष अदालत से तलाशी वारंट प्राप्त कर व्यापक छापेमारी शुरू की।

विशेष न्यायालय निगरानी, पटना से अनुमति मिलने के बाद पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने शनिवार सुबह एक साथ पटना और जमुई में छापेमारी शुरू की। राजधानी पटना के मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित ज्योतिपुरम इलाके में जगत विला अपार्टमेंट के फ्लैट की बारीकी से तलाशी ली गई। इसके अलावा कंकड़बाग के पूर्वी इंदिरा नगर रोड नंबर-4 स्थित आवास पर भी जांच एजेंसी कई घंटों तक दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच करती रही।

सूत्रों के अनुसार ईओयू की टीम ने घरों में मौजूद अलमारी, लॉकर, बैंक दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागजात, बीमा पॉलिसियां, निवेश फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की गहन जांच की। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अधिकारियों ने बरामद सामग्री को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। ईओयू का कहना है कि सभी दस्तावेजों की जांच और मिलान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।

कार्रवाई केवल आवासीय परिसरों तक सीमित नहीं रही। जमुई जिले में केकेएम कॉलेज के पास स्थित अभियंता के किराये के आवास पर भी टीम ने छापेमारी की। इसके साथ ही झाझा स्थित ग्रामीण कार्य प्रमंडल कार्यालय में भी तलाशी ली गई। कार्यालय से कई फाइलें और विभागीय रिकॉर्ड की जांच की गई। ईओयू की टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अभियंता के कार्यकाल के दौरान किन-किन परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितताएं हुईं और क्या विभागीय प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति अर्जित की गई।

ग्रामीण कार्य विभाग राज्य में सड़कों, पुलों और ग्रामीण आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस विभाग में करोड़ों रुपये की योजनाओं का संचालन होता है। ऐसे में किसी अभियंता पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगना विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। ईओयू अब यह भी जांच कर रही है कि अभियंता ने किन ठेकेदारों और कंपनियों के साथ काम किया और क्या किसी प्रकार का आर्थिक लाभ लेकर परियोजनाओं में अनियमितताएं की गईं।

सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी अभियंता के बैंक खातों और निवेश पैटर्न का विस्तृत विश्लेषण कर रही है। कई निजी और संयुक्त खातों की जानकारी भी खंगाली जा रही है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति होने की भी जांच की जा रही है। अक्सर आय से अधिक संपत्ति के मामलों में आरोपी अधिकारी अपनी संपत्तियां रिश्तेदारों या परिचितों के नाम पर खरीदते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ईओयू संपत्ति खरीद से जुड़े दस्तावेजों और लेन-देन की श्रृंखला की जांच कर रही है।

छापेमारी के दौरान ईओयू अधिकारियों ने डिजिटल डेटा पर भी विशेष ध्यान दिया। लैपटॉप, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को स्कैन किया गया। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि डिजिटल रिकॉर्ड से वित्तीय लेन-देन, निवेश और अन्य संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी अहम जानकारी मिल सकती है। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में डिजिटल साक्ष्य को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अधिकांश आर्थिक लेन-देन ऑनलाइन माध्यम से किए जाते हैं।

बिहार में पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक अपराध इकाई ने कई बड़े अधिकारियों, इंजीनियरों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीति अपनाने के बाद ईओयू लगातार सक्रिय भूमिका में दिखाई दे रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामलों में जांच एजेंसियां अब केवल शिकायतों पर निर्भर नहीं रह रही हैं, बल्कि वित्तीय प्रोफाइलिंग और गुप्त निगरानी के आधार पर भी कार्रवाई की जा रही है। गोपाल कुमार के खिलाफ हुई कार्रवाई को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस छापेमारी की चर्चा तेज हो गई है। कई लोगों का मानना है कि यह कार्रवाई सरकारी अधिकारियों के लिए एक बड़ा संदेश है कि भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामलों में अब सख्ती बढ़ रही है। वहीं आम लोगों के बीच भी यह उम्मीद जगी है कि सरकारी योजनाओं में होने वाली वित्तीय अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

ईओयू अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जांच प्रारंभिक चरण में है और बरामद दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद मामले में कई नए खुलासे हो सकते हैं। यदि जांच में और अधिक संपत्ति या वित्तीय अनियमितताओं के प्रमाण मिलते हैं तो अभियंता के खिलाफ कानूनी शिकंजा और कस सकता है। जांच एजेंसी संबंधित विभागों, बैंकों और राजस्व अभिलेखों से भी जानकारी जुटा रही है ताकि संपत्तियों का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि आय से अधिक संपत्ति के मामलों में जांच काफी जटिल होती है क्योंकि इसमें वर्षों पुराने वित्तीय रिकॉर्ड, निवेश और संपत्ति खरीद की पड़ताल करनी पड़ती है। कई बार आरोपी अधिकारी संपत्ति को अलग-अलग माध्यमों और लोगों के नाम पर छिपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों में बैंकिंग रिकॉर्ड, आयकर विवरण, संपत्ति पंजीकरण और डिजिटल डेटा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईओयू इसी दिशा में व्यापक जांच कर रही है।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत को सामने ला दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय-समय पर संपत्ति का ऑडिट और निगरानी तंत्र मजबूत किया जाए तो भ्रष्टाचार के मामलों को काफी हद तक रोका जा सकता है। साथ ही विभागीय कार्यप्रणाली में तकनीकी निगरानी और ऑनलाइन पारदर्शिता बढ़ाने से भी अनियमितताओं पर नियंत्रण संभव है।

फिलहाल ईओयू की टीम जब्त दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच में जुटी हुई है। आने वाले दिनों में जांच के आधार पर और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो अभियंता के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस छापेमारी ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि बिहार में भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ रहा है और जांच एजेंसियां अब बड़े अधिकारियों पर भी सख्त नजर रख रही हैं।

साबरकाँठा जिले में निर्मित ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क पर्यटकों में जगा रहा है आकर्षण, 2 महीनों में 3000 से अधिक लोग आए

▸▸ 5,930 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित यह पार्क गुजरात से गुजरने वाली कर्क रेखा के भौगोलिक एवं खगोलीय महत्व के बारे में जानकारी देता है

▸▸ एक सेल्फ-एक्सप्लेनेटरी पार्क; जहाँ एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स तथा आगंतुकों के लिए सुविधा उपलब्ध, गर्मी की छुट्टियों को बनाएगा दिलचस्प

गांधीनगर : गुजरात के नागरिक और विशेषकर विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने तथा गुजरात से गुजरने वाली कर्क रेखा के भौगोलिक महत्व के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत कार्यरत 'गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (गुजकोस्ट) द्वारा साबरकाँठा जिले में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क का निर्माण किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा गत 11 मार्च, 2026 को साबरकाँठा जिले के सलाल गाँव में इस पार्क का उद्घाटन किया गया था, जो राज्य में विज्ञान विषय की शिक्षा तथा जागरूकता को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वैज्ञानिक रुझानों /झुकावों को प्रोत्साहन देने और बच्चों में आधुनिक विज्ञान की क्षमताओं के बारे में समझ विकसित करने पर सदैव बल दिया है।

यह साइंस पार्क आगंतुकों के लिए विज्ञान पर्यटन के केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। पर्यटकों में और विशेष रूप से विज्ञान में रुचि रखने वाले आगंतुकों में यह पार्क अब अनूठा आकर्षण उत्पन्न कर रहा है। उद्घाटन होने के बाद 2 महीने की समयावधि में लगभग 3500 से अधिक आगंतुक टॉपिक ऑफ साइंस पार्क देखने के लिए आ चुके हैं और इस समय जब गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, तब आगंतुकों की संख्या में वृद्धि होगी।

8 करोड़ रुपए की लागत से 5,930 वर्ग मीटर में विकसित साइंस पार्क

उल्लेखनीय है कि गुजकोस्ट द्वारा 8 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लगभग 5,930 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित किए गए इस पार्क के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा था कि नागरिकों तथा विशेषकर विद्यार्थियों में वैज्ञानिक रुझान / झुकाव विकसित करने के लिए ऐसी पहलें महत्वपूर्ण हैं।

यह पार्क कर्कवृत्त तथा कर्क रेखा के भौगोलिक एवं खगोलीय महत्व को समझाने के लिए एक इंटरेक्टिव शैक्षिणक तथा अनुसंधान केन्द्र के रूप में सेवा देगा, जिसमें पृथ्वी व सूर्य के बीच के संबंध तथा ऋतुगत परिवर्तन शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश पृथ्वी के ऐसे भाग हैं, जो पृथ्वी के केन्द्र के निकट हैं और अति समृद्ध जैवविविधताओं से युक्त हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश लगभग 40 प्रतिशत भूमि क्षेत्र को समाविष्ट करते हैं, जो कर्कवृत्त तथा मकरवृत्त के बीच आता है।

ट्रॉपिक ऑफ सेंटर (टीओसी) यानी कर्कवृत्त हमारी पृथ्वी को विभाजित करने वाले पाँच मुख्य अक्षांश वृत्तों में एक है, जिसे उत्तरीय उष्णकटिबंध के रूप में भी जाना जाता है। वह पृथ्वी पर स्थित सबसे उत्तरीय अक्षांश वृत्त है, जहाँ सूर्य उसकी पराकाष्ठा पर सीधे सिर के ऊपर देखा जा सकता है।

कर्क रेखा गुजरात के सात जिलों से गुजरती है

कर्कवृत्त विषुववृत्त से 23.50 डिग्री उत्तर के कोण पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है; जो भारत सहित 16 देशों, 3 महाद्वीपों तथा विश्वभर के 6 जल संग्रहों से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा आठ राज्यों से गुजरती है; जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम शामिल हैं।

गुजरात में जिन सात जिलों से कर्क रेखा गुजरती है; उनमें (1) अरवल्ली, (2) साबरकाँठा, (3) गांधीनगर, (4) मेहसाणा, (5) सुरेन्द्रनगर, (6) पाटण तथा (7) कच्छ शामिल हैं। कर्क रेखा गुजरात की उत्तरीय सीमा से गुजरती है, जिसके कारण राज्य में बहुत ही गर्म या बहुत ही ठंडा वातावरण रहता है।

कर्कवृत्त (टीओसी) तथा उसके महत्व के बारे में जागरूकता तथा समझ विकसित करने और इस साइट को एक शोध केन्द्र (एक्सप्लोरेशन पॉइंट) के रूप में विकसित करने के लिए साबरकाँठा जिले में हिम्मतनगर राजमार्ग पर यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क विकसित किया गया है।

खुले आकाश तले विज्ञान की जीवंत प्रयोगशाला

ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ विज्ञान को केवल पढ़ा ही नहीं जाता, बल्कि अनुभव भी किया जा सकता है। पार्क में विभिन्न प्रदर्शनियों तथा उपकरणों द्वारा आगंतुकों को समझाया जाता है कि पृथ्वी का झुकाव ऋतुओं को किस प्रकार प्रभावित करता है, वर्ष के दौरान सूर्य की गति एवं छाया में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, सन डायल द्वारा समय तथा सूर्य की स्थिति किस तरह मापी जा सकती है, आदि बातें विद्यार्थियों के लिए इस स्थल को एक खुली हवा में स्थित विज्ञान की प्रयोगशाला बना देती हैं।

विज्ञान पर्यटन, ज्ञान का आकर्षण

इस पार्क को एक अनूठे तथा सेल्फ-एक्सप्लेनेटरी प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है; जिसमें बाह्य प्रदर्शनियाँ, खगोलीय ढाँचे (एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स) तथा आगंतुकों के लिए सुविधा है। यह पार्क विज्ञानप्रेमियों के लिए एक आकर्षक स्थल बन गया है। आगंतुकों के लिए यहाँ विभिन्न दिलचस्प गतिविधियाँ हैं, जैसे कि वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा पर खड़े रहने का अनुभव, रुचिप्रद विज्ञान प्रदर्शनी, प्राकृतिक द्रव्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि। इसके साथ; यह पार्क स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार एवं विकास के नए अवसर भी पैदा करता है। यह पार्क विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए एक जीवंत केन्द्र समान है। इस प्रकार; ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क गुजकोस्ट द्वारा एक अनूठी वैज्ञानिक व शैक्षणिक पहल है; जो आगंतुकों के लिए एक अमूर्त भौगोलिक विचार को मूर्त, आकर्षक व सूचनाप्रद अनुभव में परिवर्तित करती है। गुजरात में यह पार्क एक माइल स्टोन समान है, जो वैज्ञानिक जिज्ञासा को जागृत करेगा। यह पार्क वैज्ञानिक जाति, अनुभवजन्य शिक्षा तथा नवीनता-संचालित सार्वजनिक जुड़ाव को प्रोत्साहन देने की गुजरात की प्रतिबद्ध को मजबूत बनाता है।

पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने भावनगर मंडल का संरक्षा निरीक्षण किया

पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने दिनांक 14 एवं 15 मई, 2026 को भावनगर मंडल के बोटाद–भावनगर खंड का विस्तृत संरक्षा निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य रेल संरक्षा, परिचालन दक्षता तथा यात्री सुविधाओं की समीक्षा करना था।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 14 मई, 2026 को अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने बोटाद से भावनगर परा तक विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया तथा मार्ग में रेल पथ, सिग्नल एवं अन्य संरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।

इसी दिन उनके करकमलों द्वारा भावनगर परा में नवनिर्मित टाइप-V रेलवे आवासों (5 इकाइयों) का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति रेलवे की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए वृक्षारोपण भी किया गया।

निरीक्षण के दौरान उनके साथ मंडल रेल प्रबंधक दिनेश वर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक ऋत्विक शर्मा तथा मंडल के सभी शाखा अधिकारी उपस्थित रहे।

इसके पश्चात अपर महाप्रबंधक ने भावनगर टर्मिनस रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में शाखा अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विकास कार्यों, संरक्षा उपायों एवं परिचालन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। साथ ही नवनिर्मित मंडल कार्यालय भवन का भी अवलोकन किया।

दिनांक 15 मई, 2026 को श्री प्रदीप कुमार ने बोटाद रेलवे स्टेशन का संरक्षा निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन पर उपलब्ध संरक्षा एवं यात्री सुविधाओं की समीक्षा की गई। इसी दिन उनके करकमलों द्वारा बोटाद में नवनिर्मित रेलवे सुरक्षा बल कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। निरीक्षण के समय मंडल के संबंधित शाखा अधिकारी भी उपस्थित रहे।

इस दो दिवसीय निरीक्षण के दौरान अपर महाप्रबंधक ने संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए तथा भावनगर मंडल में अधोसंरचना विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं यात्री सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

29 मई से 26 जून तक प्रत्येक शुक्रवार को भावनगर टर्मिनस–शकूर बस्ती के बीच चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा भावनगर मंडल से एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त रेल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। भावनगर टर्मिनस और शकूर बस्ती के बीच विशेष किराये पर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, भावनगर मंडल श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार, इस विशेष ट्रेन का संचालन निम्नानुसार किया जाएगा—

ट्रेन संख्या 09257 भावनगर टर्मिनस–शकूर बस्ती साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 29 मई, 2026 से 26 जून, 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को भावनगर टर्मिनस से दोपहर 14:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन शनिवार को प्रातः 10:55 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 09258 शकूर बस्ती–भावनगर टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 30 मई, 2026 से 27 जून, 2026 तक प्रत्येक शनिवार को शकूर बस्ती से दोपहर 13:15 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन रविवार को प्रातः 08:50 बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी।

दोनों दिशाओं में यह ट्रेन निम्नलिखित स्टेशनों पर ठहरेगी— भावनगर परा, सिहोर (गुजरात), धोला, बोटाद, धंधुका, धोलका, सरखेज, गांधीग्राम, चांदखेड़ा रोड, मेहसाणा जंक्शन, पालनपुर जंक्शन, आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर जंक्शन, किशनगढ़, फुलेरा, रिंगस, नीम का थाना, नारनौल, रेवाड़ी जंक्शन, गुड़गांव एवं दिल्ली कैंट।

इस विशेष ट्रेन में द्वितीय श्रेणी, शयनयान, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी तथा सेकंड एसी श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09257 के लिए टिकटों की बुकिंग 17 मई, 2026 (रविवार) से सभी यात्री आरक्षण केन्द्रों तथा IRCTC की वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन के समय, ठहराव एवं संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु 'EASE' टीम का शुभारंभ

पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल ने महिला सशक्तिकरण, कल्याण एवं सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण एवं प्रगतिशील पहल करते हुए EASE (Empowerment Advocates and Support Enhancement) टीम का शुभारंभ किया है। यह पहल मुंबई सेंट्रल मंडल की अपर मंडल रेल प्रबंधक (एडीआरएम) डॉ. आरती सिंह परिहार के मार्गदर्शन में की गई है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मंडल के विभिन्न विभागों से महिला प्रतिनिधियों को इस टीम के सदस्य के रूप में नामित किया गया है, ताकि मंडल के सभी विभागों एवं कार्यक्षेत्रों की व्यापक भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

EASE टीम नियमित रूप से मुंबई मंडल के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों, कार्यालयों तथा विभिन्न कार्यस्थलों का दौरा कर महिला कर्मचारियों एवं स्टाफ सदस्यों के साथ प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करेगी। इन संवादों के माध्यम से महिला कर्मचारियों के विचारों, चिंताओं, चुनौतियों तथा सुझावों को अधिक सहज एवं सकारात्मक वातावरण में समझने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही, ऐसे संवादों के माध्यम से टीम महिला कर्मचारियों को व्यक्तिगत विकास, व्यावसायिक उन्नति, आत्मविश्वास निर्माण तथा नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए प्रोत्साहित, प्रेरित एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

इस पहल का उद्देश्य एक सुरक्षित, समावेशी, सहयोगात्मक एवं सशक्त कार्य वातावरण को प्रोत्साहित करना भी है, जहाँ महिला कर्मचारी स्वयं को सम्मानित, समर्थित तथा प्रोत्साहित महसूस करें और अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।

EASE टीम का गठन लैंगिक समावेशिता को और अधिक सुदृढ़ करने, कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देने तथा सकारात्मक एवं प्रगतिशील कार्य संस्कृति के निर्माण के प्रति पश्चिम रेलवे की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।

बिलासपुर मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते पोरबंदर से चलने वाली दो जोड़ी ट्रेनें रद्द

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली स्थापित करने हेतु किए जा रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल से होकर चलने वाली दो जोड़ी ट्रेनों को रद्द किया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार, रद्द की जाने वाली ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

रद्द की गई ट्रेनें:

1. 10.06.2026 एवं 11.06.2026 को पोरबंदर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 12905 पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
2. 12.06.2026 एवं 13.06.2026 को शालीमार से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 12906 शालीमार-पोरबंदर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
3. 12.06.2026 को पोरबंदर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 12949 पोरबंदर-सांतरागाछी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
4. 14.06.2026 को सांतरागाछी से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 12950 सांतरागाछी-पोरबंदर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

15 जून को अहमदाबाद मंडल, पश्चिम रेलवे में पेंशन अदालत का आयोजन

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबन्धित प्रश्नों के त्वरित निपटारे के लिए 15 जून, 2026 (सोमवार) को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा।

वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी श्री सिद्धार्थ के अनुसार अहमदाबाद मण्डल से जो भी कर्मचारी सेवानिवृत हुए है उन पेंशनर/फेमिली पेंशनर के पेंशन संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय अहमदाबाद में दिनांक 15.06.2026 (सोमवार) को पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है।

अहमदाबाद मंडल से जो भी कर्मचारी रेल सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं वह पेंशनर/फैमिली पेंशनर अपनी पेंशन संबंधित शिकायतें है वह अपना आवेदन (तीन प्रतियों में) दिनांक 01.06.2026 तक मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय (स्थापना), अहमदाबाद मण्डल पश्चिम रेलवे, GCS हॉस्पिटल के सामने अमदुपुरा अहमदाबाद को भेज सकते हैं।

आवेदन में अपना नाम, पदनाम, अंतिम वेतन, भर्ती तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि PPO प्रति एवं शिकायत का प्रकार अवश्य दर्ज करें।

अहमदाबाद–धोलेरा के बीच बनेगा 134 किमी लंबा ब्रॉड गेज सेमी हाई-स्पीड कॉरिडोर

▸▸ साबरमती, गांधीग्राम एवं वस्त्रापुर स्टेशनों पर मेट्रो नेटवर्क से होगा कनेक्ट

▸▸ विधायक श्री अमित ठाकर और डीआरएम श्री वेद प्रकाश ने किया वस्त्रापुर स्टेशन का दौरा

गुजरात को देश का पहला ब्रॉड गेज सेमी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर मिलने जा रहा है। अहमदाबाद (सरखेज) से धोलेरा के बीच लगभग 134 किलोमीटर लंबी दोहरी ब्रॉड गेज सेमी हाई-स्पीड रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना अहमदाबाद, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (SIR), आगामी धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (National Maritime Heritage Complex) को अत्याधुनिक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। परियोजना की डिज़ाइन गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा तथा परिचालन गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

इस परियोजना के अंतर्गत साबरमती, गांधीग्राम एवं वस्त्रापुर स्टेशनों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। साथ ही साबरमती स्टेशन पर बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी तथा मोरैया स्टेशन पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) से जुड़ाव सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे गुजरात एक विश्वस्तरीय मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित होगा।

इसी क्रम में वेजलपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री अमित ठाकर ने वस्त्रापुर स्टेशन का दौरा किया। इस अवसर पर मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में माननीय विधायक श्री अमित ठाकर ने कहा कि जब किसी राज्य में बड़े विकास कार्य होते हैं, तब उससे जुड़े क्षेत्रों में भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। उन्होंने कहा कि धोलेरा में विकसित हो रहे विशाल औद्योगिक एवं आर्थिक क्षेत्र को अहमदाबाद के सरखेज क्षेत्र से जोड़ने वाली यह सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना गुजरात के विकास को नई दिशा देगी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री तथा क्षेत्र के सांसद श्री अमित शाह तथा रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 20,667 करोड़ की इस परियोजना से वेजलपुर क्षेत्र एवं अहमदाबाद शहर में व्यापक विकास और निवेश की संभावनाएं उत्पन्न होंगी।

मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से लोग मात्र 45 मिनट में धोलेरा पहुँच सकेंगे, जिससे रोजगार, आवासीय एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को अभूतपूर्व गति मिलेगी। साथ ही भावनगर क्षेत्र में विकसित हो रहे बंदरगाह एवं औद्योगिक गतिविधियों से भी अहमदाबाद और सरखेज क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

यह परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित की जा रही है, जिसका उद्देश्य मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाना तथा भारत की लॉजिस्टिक दक्षता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।

हड़ताल से ठप हुई शिमला की सफाई व्यवस्था, 60 हजार घरों का कूड़ा सड़कों पर; मेयर ने वेतन बढ़ोतरी का दिया भरोसा

Shimla। पर्यटन नगरी शिमला में सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने शहर की स्वच्छता व्यवस्था को गंभीर संकट में डाल दिया है। हड़ताल के दूसरे ही दिन हालात ऐसे हो गए कि राजधानी के करीब 60 हजार घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कूड़ा नहीं उठ पाया। शहर के कई प्रमुख बाजारों, रिहायशी इलाकों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरे के ढेर जमा होने लगे हैं, जिससे लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ते कचरे और दुर्गंध के बीच अब स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी गहराने लगे हैं।

सैहब सोसायटी के तहत कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर काम बंद कर रखा है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं को लेकर उनकी मांगें लंबित हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी नाराजगी के चलते कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी, जिसका सीधा असर पूरे शहर की सफाई व्यवस्था पर दिखाई देने लगा है।

शिमला जैसे पहाड़ी और पर्यटन आधारित शहर में नियमित कूड़ा उठाव व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहां रोजाना बड़ी मात्रा में घरेलू और व्यावसायिक कचरा निकलता है। लेकिन सफाई कर्मियों के काम पर नहीं लौटने से अब सड़क किनारे कूड़े के ढेर जमा होने लगे हैं। स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कई बाजारों में कूड़े से बदबू फैलने लगी है और लोगों ने प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की मांग की है।

स्थिति को संभालने के लिए नगर निगम ने वैकल्पिक व्यवस्था लागू की है। निगम प्रशासन ने सभी वार्डों में अस्थायी फोकल प्वाइंट बनाए हैं, जहां लोग अपना कूड़ा जमा कर सकते हैं। इन स्थानों से वाहनों के माध्यम से कचरा उठाने की व्यवस्था की गई है। हालांकि लगातार बढ़ते कचरे और सीमित संसाधनों के कारण यह व्यवस्था पूरी तरह प्रभावी साबित नहीं हो पा रही है। कई इलाकों में फोकल प्वाइंट के आसपास भी कचरा जमा होने लगा है।

बढ़ते संकट के बीच मेयर सुरेंद्र चौहान ने हड़ताली कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नगर निगम कर्मचारियों की समस्याओं को समझता है और उनकी कई मांगों पर सकारात्मक विचार किया जा रहा है। मेयर ने संकेत दिया कि सफाई कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला नगर निगम की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में लिया जाएगा।

मेयर ने यह भी कहा कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद कर्मचारियों की मांगों पर औपचारिक निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि नगर निगम ने हाल के वर्षों में सफाई कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। पहली बार सफाई कर्मियों के लिए 30 लाख रुपये तक का बीमा लागू किया गया है। इसके अलावा दिवाली बोनस बढ़ाकर 2000 रुपये किया गया और कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों तथा अन्य सुविधाओं में भी विस्तार किया गया है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि वह कर्मचारियों के साथ लगातार संवाद बनाए हुए है और जल्द समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अब भी अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा और जब तक लिखित रूप में फैसला नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले ही आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम यानी एस्मा लागू कर दिया है। इसके तहत आवश्यक सेवाओं में शामिल कर्मचारियों की हड़ताल को प्रतिबंधित किया जा सकता है। हालांकि एस्मा लागू होने के बावजूद बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी आंदोलन पर डटे हुए हैं। इससे प्रशासन के सामने चुनौती और बढ़ गई है।

शिमला की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर करती है। ऐसे में शहर में फैला कचरा और बिगड़ती सफाई व्यवस्था पर्यटन छवि को भी नुकसान पहुंचा सकती है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो पर्यटकों की संख्या पर असर पड़ सकता है।